

## चीनी एप्स पर प्रतबंध

### प्रलिम्स के लयि:

भारत और उसके पड़ोसी देशों की अवस्थति।

### मेन्स के लयि:

चीनी एप्स पर प्रतबंध लगाने का आर्थिक प्रभाव, सरकारी नीतयिँ और हस्तक्षेप, भारत-चीन संबंध ।

## चरचा में क्योँ?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने 54 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतबंध लगाने की सफिरशि की है, जसिमें लोकप्रयि गेम 'गरेना फ्री फायर' भी शामिल है, जो गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधति चतिाओं को उत्पन्न करता है ।

- वर्ष 2020 में सरकार ने **टकिटॉक** और चीन के अन्य लोकप्रयि लघु वीडयो एप पर भी प्रतबंध लगा दयिा ।
- भारत में ऐसे एप्स पर प्रतबंध लगाने का नरिणय न केवल एक भू-राजनीतिक कदम है, बल्कि एक रणनीतिक व्यापार पैतरेबाज़ी भी है जसिका महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव हो सकता है ।
- इससे पहले यह देखा गया था कि वर्ष 2021 में चीन के साथ भारत का व्यापार 125 बलियिन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया था, जसिमें चीन से 100 बलियिन अमेरिकी डॉलर का रकिॉर्ड आयात कयिा गया, जो भारत में चीनी सामानों, वशिष रूप से मशीनरी की एक शृंखला की नरितर मांग को रेखांकति करता था ।



## नरिणय के लाभ:

- **राष्ट्र के तकनीकी बाज़ार में सहायता:**
  - इन चीनी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को भारतीय जनता के लयि प्रतबंधति करने से हमारी घरेलू आईटी प्रतभिा को अवसर प्रदान करने तथा इंटरनेट उपयोगकर्त्ता पर ध्यान केंद्रति करने में मदद मिलती है ।
  - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सलिकिॉन वैली (US) तथा चीन की बड़ी टेक फर्म भारतीय उपभोक्ताओं को लेकर असमंजस्य में हैं, लेकनि भारत का ध्यान अपने देश के तकनीकी बाज़ार की बजाय आईटी सेवाओं के नरियात पर ज़्यादा रहता है ।
- **पैसवि डपिलोमेसी पर अब कोई भरोसा नहीं:** इन एप्स पर प्रतबंध लगाने से भारत की ओर से भी एक स्पष्ट संदेश जाता है कि यह अब चीन की नबिल एंड नेगोशिएटि पॉलिसी का शकिार नहीं होगा ।

- लद्दाख में गतरिध जारी है।
- चीन की महत्त्वाकांक्षा को चोट पहुँचाना: यह प्रतर्बिध चीन के सबसे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक अर्थात् 21वीं सदी की डिजिटल महाशक्ति बनना, को प्रभावित कर सकता है।
- दुनिया के बाकी हिस्सों में नयित्रण स्थापित करने के अपने प्रयास में चीनी इंटरनेट उद्योग को आर्टफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के लिये एक प्रशिक्षण को जारी रखने हेतु भारत के 500 मिलियन से अधिक नेटज़िन्स (Netizens) की आवश्यकता है।
- डेटा के महत्त्व को पहचानना: भारत द्वारा एप्स पर प्रतर्बिध और दूरसंचार हार्डवेयर एवं मोबाइल हैंडसेट से संबंधित प्रतर्बिधों पर विचार करना डेटा संग्रह एवं डिजिटल तकनीक के लिये मददगार साबित हो सकता है।

## नरिणय के वपिकष में तरक:

- डेटा गोपनीयता चीनी एप्स तक सीमति नहीं: हाल के दिनों में अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा की चोरी करने और भारत से बाहर के सर्वरों तक पहुँचाने की रपिर्ट के बाद एप्स पर प्रतर्बिध लगा दिया गया था।
  - हालाँकि डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा चिंता केवल चीनी एप्स तक ही सीमति नहीं हैं।
- चीन पर भारत की आर्थिक नरिभरता: चीनी मोबाइल एप्स पर प्रतर्बिध अपेक्षाकृत छोटा लक्ष्य है क्योंकि भारत कई महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में चीन के उत्पादों पर नरिभर है।
- प्रतर्स्थापन का अभाव: 118 से अधिक चीनी एप्स को प्रतर्बिधित करने के बाद भारतीय तकनीकियों के माध्यम से अन्य वेबसाइटों और एप्लीकेशन द्वारा इस कमी को दूर करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन यह चीनी वेबसाइटों और एप्लीकेशन के उपयोग को रोकने में सक्षम नहीं है।

## आगे की राह

- प्राथमिक स्तर की भारतीय आईटी फर्मों को दूसरों को अपनी सेवा उपलब्ध कराने के बजाए देश में ही सेवाओं को प्रदान करना चाहिये।
- चीनी तकनीक की अनुपस्थिति में भारतीय उद्यमियों को मौजूदा फर्मों द्वारा अब तक प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को परिवर्तित रूप में नहीं देखना चाहिये बल्कि उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली उन सेवाओं एवं उत्पाद प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जिनका देश भर में भारतीयों द्वारा रोज़मर्रा उपयोग किया जाएगा।
  - नेटज़िन्स को विभिन्न बाज़ारों में उपलब्ध समान सेवाएँ प्रदान करने का उद्देश्य काफी व्यापक है, वही हमारे देश में भाषायी क्षेत्रीय बाधाएँ भी मौजूद हैं।
  - यह एक वशिष्ट प्रकार के छोटे बाज़ारों के विकास का अवसर प्रदान करता है, जहाँ स्थानीय समुदाय द्वारा स्थानीय लोगों के लिये उपलब्ध कराई गई वशिष्ट इंटरनेट सेवाएँ मौजूद होंगी।
- नए डिजिटल उत्पादों के लिये मूलतः अति-क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर लगातार बढ़ते बाज़ार में उभरने की योजना बनानी चाहिये।
  - उदाहरण के लिये ऐसे एप विकसित किये जा सकते हैं, जो वशिष्ट बाज़ार मूल्य, स्थानीय ट्रेन और बस मार्ग से संबंधित सूचना प्रदान करते हों या फरि गैर-पारंपरिक बैंकिंग एवं उधार, शक्ति, स्वास्थ्य, ऑनलाइन बकिरी, वर्गीकृत वजिज़ापन आदि की अनुमति दिते हों।

## स्रोत: द हट्टि

## कशिशर न्याय प्रणाली

### प्रलिमिस के लिये:

बच्चों से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान, बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

### मेन्स के लिये:

कशिशर न्याय प्रणाली का विकास, कशिशर न्याय प्रणाली का उद्देश्य, बच्चों से संबंधित मुद्दे।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक नरिणय को चुनौती देने वाली एक अपील को खारजि करते हुए कहा कि कशिशर न्याय संबंधी याचिकाओं को प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिये।

- न्यायालय ने कहा कि यदि कशिशर होने की प्रमाणिकता के लिये संदिग्ध प्रकृति के दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाते हैं, तो आरोपी को कशिशर नहीं माना जाएगा, यह देखते हुए कि यह कानून एक लाभकारी कानून है।

- गौरतलब है कि कश्शोर अपराधियों (18 वर्ष से कम आयु) को 'कश्शोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000' के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- इस अधिनियम की धारा 7A के तहत एक आरोपी व्यक्ति 'कश्शोर होने का दावा' किसी भी न्यायालय के समक्ष, किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि मामले के अंतिम नपिटान के बाद भी कर सकता है।

## भारत में वकिसति कश्शोर न्याय प्रणाली:

- **कश्शोर न्याय प्रणाली की परभाषा:** कश्शोर न्याय प्रणाली उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन किया है और जिन्हें देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है।
  - भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को कश्शोर माना जाता है।
  - अवयस्क वह व्यक्ति है, जिसने पूर्ण कानूनी उत्तरदायित्व संबंधी आयु प्राप्त नहीं की है और कश्शोर एक ऐसा अवयस्क है जिसने कोई अपराध किया है और उसे देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता है।
  - भारत में 7 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को 'डॉक्टरनि ऑफ डोली इनकैपैक्स' के कारण किसी भी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अपराध करने का इरादा रखने में असमर्थ व्यक्ति।
- कश्शोर न्याय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य युवा अपराधियों का पुनर्वास और उन्हें दूसरा अवसर प्रदान करना है।
  - इस सुरक्षा का मुख्य कारण यह है कि बच्चों का मसुतषिक पूरी तरह से वकिसति नहीं होता है और उनमें गलत एवं सही की पूरी समझ नहीं होती है।
  - यह सथति तब उत्पन्न होती है जब माता-पति उचित पालन-पोषण करने में असमर्थ होते हैं और घरों में हसिा की घटनाएँ होती हैं या 'एकल पेरेंट' जो अपने बच्चों को लंबे समय तक असुरक्षित छोड़ देते हैं।
  - समाचार, फलिमें, वेब सीरीज़, सोशल मीडिया और शकिसा की कमी का प्रभाव भी बच्चों के आपराधिक गतविधियों में लपित होने का कारण है।
- भारत की स्वतंत्रता के बाद संवधान ने बच्चों की सुरक्षा और वकिसा के लिये [मौलिक अधिकारों](#) एवं [राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों](#) के तहत कुछ प्रावधान किये।
- **बाल अधिनियम, 1960:** इस अधिनियम ने किसी भी परसिथति में बच्चों के कारावास को प्रतबिधति किया और देखभाल, कल्याण, प्रशकिसण, शकिसा, रखरखाव, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान किया।
- **कश्शोर न्याय अधिनियम, 1986:** बाल अधिनियम को एकरूपता प्रदान करने हेतु कश्शोर न्याय अधिनियम, 1986 लागू किया गया, साथ ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1959 के अनुसार, कश्शोरों की सुरक्षा के लिये मानक नरिधारति किये गए।
  - 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया।
- **कश्शोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000:** भारत सरकार द्वारा कश्शोर न्याय अधिनियम (JJA) को नरिसुत कर एक नया अधिनियम, कश्शोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लाया गया।
  - इसमें 'कानून के साथ वविाद' और 'देखभाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता' जैसी बेहतर शब्दावली थी।
  - जनि कश्शोरों का कानून के साथ टकराव होता है, उन्हें कश्शोर न्याय बोर्ड द्वारा नरियंत्रति किया जाता है और जनि कश्शोरों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा नरियंत्रति किया जाता है।
  - वर्ष 2006 में कश्शोर अधिनियम में कश्शोरों को अपराध करने की तथिसि से माने जाने के लिये संशोधन किया गया था।
- **कश्शोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** इसने कश्शोर अधिनियम, 2000 को प्रतसिथापति किया है।
  - इस अधिनियम को संसद में काफी वविाद और वरिोध के बाद पारति किया गया था। इसके द्वारा मौजूदा कानून में कई बदलाव किये गए हैं।
  - इस अधिनियम के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16-18 आयु वर्ग के कश्शोरों को वयस्कों के रूप में माना गया है।
  - कश्शोर न्याय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और समाज की बदलती परसिथतियों के अनुसार बनाया गया है।
  - अधिनियम अनाथ, परतियक्त, आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की स्पष्ट परभाषा देने के साथ उनके लिये एक संगठित प्रणाली प्रदान करता है।
- **कश्शोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021:** हाल ही में कश्शोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन वधियक, 2021 राज्यसभा में पारति किया गया है।
  - यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों को मज़बूत करने तथा कारगर बनाने का प्रयास करता है।
  - न्यायालय के समक्ष गोद लेने के कई मामले लंबति हैं तथा न्यायालय की कार्यवाही में तीव्रता लाने हेतु अब शकतियों को ज़िला मजसि्ट्रेट को हसुतांतरति कर दिया गया है।
  - संशोधन में प्रावधान है कि इस तरह के गोद लेने के आदेश जारी करने का अधिकार अब ज़िला मजसि्ट्रेट के पास है।

## बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिये अन्य कानूनी ढाँचे:

- [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम \(POCSO\), 2013](#)
- [बाल शर्म \(नषिध और वनियिमन\) अधिनियम, 2016](#)
- [बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय \(UNCRC\)](#)
- [राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, 2005](#)

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

### प्रलिस के ललतः

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, राष्ट्रीय शकषा नीतल, 2020

### मेन्स के ललतः

युवाओं को शकषत करने की आवश्यकता और देश के वकलस में उनकी भूमकल, सरकारी नीतलतल और हस्तकषेप

## चरचा में कतल?

हलंल ही में सरकार ने **राष्ट्रीय शकषा नीतल 2020** और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप **प्रौढ** शकषा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु वर्ष 2022-2027 की अवधके ललतल **"नव भारत साक्षरता कार्यक्रम"** को मंजूरी दी है ।

- यह **बजट 2021-22** के अनुरूप है, जसमें संसाधनों, प्रौढ शकषा को कवर करने वाले ऑनलाइन मॉड्यूल तक पहुँच में वसतार की घोषणा की गई थी ।
- "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" का अनुमानतल कुल परवलतत 1037.90 करोड रुपए है, जसमें वर्ष 2022-27 के ललतल कर्मशः 700 करोड रुपए का केंद्रीय हसलसा और 337.90 करोड रुपए का राजतत हसलसा शामिल है ।
- देश में **प्रौढ शकषा** का नाम बदलकर अब **'सभी के ललतल शकषा'** कर दलतल गया है

## नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उददेशतः

- इस कार्यक्रम का उददेशत न केवल आधरभूत साक्षरता और अंकगणतल की शकषा प्रदान करना है बलकल उन अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरकल के ललतल आवश्यक हैं ।
- अन्य घटकों में शामिल हैं:
  - महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल (वतलतलतल साक्षरता, डजलतल साक्षरता, वाणतलतल कौशल, स्वास्थत देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल एवं शकषा, तथा परवलर कलयाण आदी) ।
  - वतलवसातल कौशल वकलस (सथानीत रोजगार प्राप्त करने की दृषुतलसे) ।
  - बुनतलदी शकषा (प्रारंभक, मधतत और माधततमक सतर की समकषता सहतल) ।
  - सतत शकषा (कला, वज्जान, प्रौद्योगकल, संस्कृतल, खेल और मनोरंजन में समग्र वतसुक शकषा पाठततक्रम, साथ ही सथानीत शकषार्थतलतल हेतु रुचकल अन्य वषतलतल का उपततग जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल पर अधकल उन्नत सामग्री सहतल) ।

## ततजना का करतलनवन

- ततजना को स्वततसेवा (Volunteerism) दतलर ऑनलाइन मीड के माधततम से लागू कतलतल जाएगा ।
  - स्वततसेवकों के प्रशकषण, अभवलनतलस, कारतलशालाओं का आततजन प्रततकष मीड के दतलर कतलतल जा सकता है । ततजना से संबंधतल सभी सामग्री और संसाधन डजलतल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे ।
- वदतलतलतल ततजना के करतलनवन हेतु इकाई होगा ।
  - वदतलतलतल का उपततग लाभार्थतलतल और स्वैचछकल शकषकों का सरवेकषण करने के ललतल कतलतल जाएगा ।

## ततजना में शामिल लोगः

- देश के सभी राजतलतल/संघ राजतल कषेतरों में 15 वर्ष और उससे अधकल आयु के गैर-साक्षर लोग ।
- राष्ट्रीय सूचना वज्जान केंद्र, NCERT और NIOS के सहततग से 'ऑनलाइन टीचगल, लरनगल ँड असेसमेंट ससलतम (OTLAS)' का उपततग करके प्रततवलरष 1 करोड की दर से 5 करोड शकषार्थतलतल का लकषत नरलधरतल कतलतल गया है ।
- **ततजना की आवश्यकताः**
- वर्ष 2011 की **जनगणना** के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधकल आयु वर्ग के नरकषरों की कुल संखतल 25.76 करोड (पुरुष 9.08 करोड, महललएँ 16.68 करोड) है ।
- साथ ही वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 तक लागू **'साक्षर भारत कार्यक्रम'** के तहत साक्षर के रूप में प्रमाणतल 7.64 करोड लोगों को धतलन में रखते हुए यह अनुमान लगतलतल गया है कवलरतमान में भारत में लगभग 18.12 करोड वतसुक नरकषर हैं ।

## इससे संबंधतल अन्य पहलेंः

- **राष्ट्रीय कौशल वकलस नगलम (NSDC)**: इसका उददेशत बडे, गुणवतततापूर्ण और लाभकारी वतलवसातल संसथानों के नरमाण को उत्तुप्रेरतल करके

कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह उद्यमों, कंपनियों और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों को वित्तपोषण प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:** यह कई मौजूदा योजनाओं का पुनर्गठन करता है, जिसके पश्चात् उन्हें सकिरनाइज़ तरीके से लागू किया जाता है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान:** यह नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ देश की सबसे बड़ी पहलों में से एक है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन:** इसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक महत्त्वपूर्ण डिजिटल साक्षरता कौशल के साथ प्रतिपरिवार कम-से-कम एक व्यक्ति को सशक्त बनाना है।
- **समग्र शिक्षा:** यह स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये पूर्व-विद्यालय से बारहवीं कक्षा तक की विद्यालयी शिक्षा हेतु एक एकीकृत योजना है।

## आगे की राह

- दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों के तहत बच्चों और कामकाजी वयस्कों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ताकि वे पढ़ना-लिखना सीख सकें। राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाओं में बच्चों हेतु विद्यालयी शिक्षा और वयस्कों के लिये साक्षरता प्रशिक्षण समानांतर रूप में शामिल होना चाहिये।

## स्रोत: द हट्टू

## ओरगामी मेटामैटेरियल्स

### प्रलिमिंस के लिये:

ओरगामी मेटामैटेरियल्स, मेटामैटेरियल्स और इसके गुण।

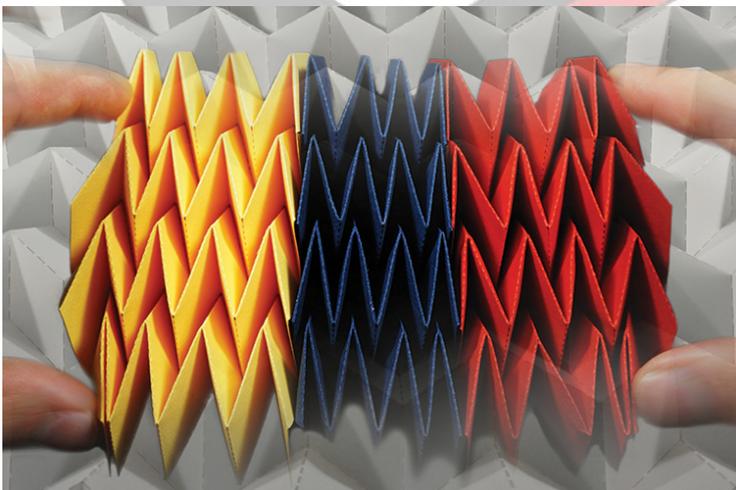
### मेन्स के लिये:

वज्जान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ।

## चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्त्ताओं ने 'ओरगामी मेटामैटेरियल्स' नामक एक नई सामग्री विकसित की है, जिसके कई महत्त्वपूर्ण उपयोग हो सकते हैं।

- इसमी पेपर फोल्डिंग (ओरगामी) की जापानी कला का उपयोग किया जाता है और वांछित गुण प्राप्त करने हेतु इसे मोड़ा जाता है।



## ओरगामी मेटामैटेरियल्स क्या है?

- शोधकर्त्ताओं ने ओरगामी मेटामैटरियल्स की एक विशेष श्रेणी विकसित की है, जो तनाव की स्थिति में भी 'पॉइसन अनुपात' का नरिंतर मूल्य प्रदर्शित करती है।
  - जब इस सामग्री को किसी विशेष दशा में खींचा जाता है, तो इसमें लंबवत, या पार्श्व, दशा में एक परिवर्तन होता है।
  - बल के साथ वरिपण और बल के पार्श्व दशा में वरिपण के बीच के अनुपात को 'पॉइसन अनुपात' कहा जाता है। पॉइसन अनुपात सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।
  - इसके प्रयोग के दौरान सामग्री को दाब के माध्यम से नष्ट करने के लिये एक नरिंतर पॉइसन अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हालाँकि वे ऐसा नहीं करने के लिये प्रवृत्त होते हैं और उनके विकृत होने पर पॉइसन अनुपात भिन्न हो जाता है।
  - इसका लाभ यह है कि परीक्षण के दौरान प्रयोग की गई वस्तु इस बात पर नरिभर नहीं करती है कि यह कागज़, बहुलक या धातु की शीट से बनाया गया है।

## मेटामैटरियल्स:

- मेटामैटरियल्स (Metamaterials) स्मार्ट सामग्री होती है जिसमें गुणों की एक वसितुत शृंखला पाई जाती है और वे एक-दूसरे से इतने भिन्न हो सकते हैं कि उनकी कोई नशिचित परिभाषा नहीं है, हालाँकि उन सभी में एक सामान्य बात यह है कि इनका नरिमाण कृत्रिम रूप से किया जाता है।
- अर्थात् वे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोगों द्वारा नरिमित हैं।

## मेटामैटरियल्स के गुण:

- कृत्रिम मूल के अलावा मेटामैटरियल्स की विशेषता यह होती है कि उनके असामान्य वदियुत चुंबकीय गुण हैं, जो उनकी संरचना और व्यवस्था के चलते पाए जाते हैं, न कि उनकी संयोजकों की वजह से।
- ये ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफीन जैसे होते हैं क्योंकि वे सभी कार्बन से नरिमित हैं, लेकिन उनकी संरचना के कारण उनके गुण बहुत भिन्न होते हैं।
- इसके महत्त्वपूर्ण गुणों में से एक मेटामैटरियल्स को भिन्न करना है, उदाहरण के लिये पदार्थ में नकारात्मक अपवर्तनांक होता है।
  - प्रकाशिकी और वदियुत चुंबकीय अनुप्रयोगों में इन पदार्थों का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

## मेटामैटरियल्स के संभावित अनुप्रयोग:

- मेटामैटरियल्स के संभावित अनुप्रयोगों में ऑप्टिकल फिल्टरिंग, चकितिसा उपकरण, रमोट एयरोस्पेस ऑपरेशन, सेंसर डिटिक्टर, सौर ऊर्जा प्रबंधन, भीड़ नयितरण, रेडोमस, ऑप्टिकल लेंस आदि शामिल हैं तथा भूकंप से संबंधित सुरक्षा उपकरणों में भी इसका उपयोग किया जाता है।
- मेटामैटरियल्स से बने लेंस का उपयोग वविरतन सीमा से नीचे इमेजिंग हेतु किया जाता है, जो परंपरागत ऑप्टिकल लेंस को और भी बेहतर बनाता है।

## स्रोत: द हद्दि

## इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत

### प्रलिमिस के लिये:

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

### मेन्स के लिये:

भारत के हतियों पर देशों की नीतियों और राजनीतिक प्रभाव, एक संगठन के रूप में OIC के साथ भारत का संबंध

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने कर्नाटक हजिाब वविाद के बीच [इस्लामिक सहयोग संगठन](#) के सांप्रदायिक वचिारों के कारण इसकी आलोचना की है।

## OIC और भारत के बीच हालिया वविाद:

- OIC का कथन: मुस्लिम छात्राओं को कर्नाटक के स्कूलों में हजिाब नहीं पहनने के लिये कहे जाने के मुद्दे पर OIC ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से "आवश्यक उपाय" अपनाने का आह्वान किया है।
  - OIC ने भारत से आग्रह किया कि वह "मुस्लिम समुदाय की जीवन-शैली के तरीकों की रक्षा करते हुए उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित

करे”।

- **भारत की प्रतिक्रिया:** भारत ने कहा कि वह एक लोकतांत्रिक देश है और देश के भीतर मुद्दों को संवैधानिक ढाँचे और तंत्र के साथ-साथ लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के अनुसार हल किया जाता है।

## इस्लामिक सहयोग संगठन:

### परिचय:

- कुल 57 देशों की सदस्यता के साथ यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।
- यह संगठन दुनिया भर में मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है।
  - यह दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण का प्रयास करता है।
- इसका गठन सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था, जिसका लक्ष्य वर्ष 1969 में एक 28 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई द्वारा येरुशलम में अल-अक्सा मस्जिद में आगजनी की घटना के बाद इस्लामीक मूल्यों को सुरक्षा प्रदान करना था।
- **मुख्यालय:** जेद्दाह (सऊदी अरब)

**What is OIC?**

OIC- Organization of the Islamic Cooperation

It was founded in **1969**

First OIC Charter Adopted in **1972**

Key Bodies of OIC:

- ▶ Council of Foreign Ministers
- ▶ General Secretariat
- ▶ Islamic Summit
- ▶ Al-Quds Committee

Number of Member Countries **57**

Founding Members **30**



## OIC के साथ भारत के संबंध:

- दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय वाले देश के रूप में भारत को वर्ष 1969 में रबात में संस्थापक सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर अपमानजनक तरीके से भारत को बाहर कर दिया गया।
- भारत कई कारणों से अब तक इस संगठन से दूर रहा:
  - भारत एक ऐसे संगठन में शामिल नहीं होना चाहता था जो धर्म के आधार पर गठित किया गया हो।
  - साथ ही जोखिम था कि सदस्य देशों के साथ व्यक्तिगत तौर पर द्विपक्षीय संबंधों में सुधार से वह एक समूह के दबाव में आ जाएगा **खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर**।

- वर्ष 2018 में **वदिश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र** में मेज़बान बांग्लादेश ने सुझाव दिया कि भारत, जहाँ दुनिया के 10% से अधिक मुसलमान रहते हैं, को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिये, लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रस्ताव का वरिध किया गया।
- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के बाद भारत समूह के किसी भी बयान पर भरोसा करने के लिये आश्वस्त है।
  - भारत ने लगातार इस बात को रेखांकित किया है कि जम्मू-कश्मीर **"भारत का अभिन्न अंग है और यह भारत का आंतरिक मामला है"** तथा इस मुद्दे पर OIC का कोई अधिकार नहीं है।
- वर्ष 2019 में भारत ने OIC के **वदिश मंत्रियों की बैठक** में **"गेस्ट ऑफ ऑनर"** के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की।
  - इस पहले निर्माण को भारत के लिये एक **कूटनीतिक जीत** के रूप में देखा गया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया था।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## वशिव सतत् विकास शिखर सम्मेलन 2022

### प्रलिस के लिये:

वशिव सतत् विकास शिखर सम्मेलन, सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारतीय पहल, बॉन चैलेंज, IUCN

### मेन्स के लिये:

समावेशी विकास, पर्यावरण प्रदूषण और गरिबत, संरक्षण, वशिव सतत् विकास शिखर सम्मेलन, सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारतीय पहल

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने **'ऊर्जा और संसाधन संस्थान'** (TERI) द्वारा आयोजित 'वशिव सतत् विकास शिखर सम्मेलन' को संबोधित किया।

## वशिव सतत् विकास शिखर सम्मेलन:

- **परिचय:**
  - वशिव सतत् विकास शिखर सम्मेलन 'ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान' (TERI) का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है।
  - यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है, जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है।
- **उद्देश्य:**
  - इसकी अवधारणा सतत् विकास और जलवायु परिवर्तन की दशा में लक्षित कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिये एकल मंच के रूप में की गई है।
  - इसका उद्देश्य सतत् विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित वैश्विक नेताओं और वदिवानों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है।

## 'ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान' (TERI):

- TERI एक गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थान है।
- यह भारत और ग्लोबल साउथ के लिये ऊर्जा, पर्यावरण एवं सतत् विकास के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1974 में टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में हुई थी और वर्ष 2003 में इसका नाम बदलकर 'ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान' कर दिया गया।

## शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष:

- **न्यायसंगत ऊर्जा पहुँच:**
  - भारत ने यह सुनिश्चित करके अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है कि गरीबों तक समान ऊर्जा पहुँच उसकी पर्यावरण नीतिकी आधारशिला बनी रहे।
  - इनमें **उज्ज्वला योजना** के तहत 90 मिलियन परिवारों की स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुँच जैसी पहल शामिल है।

- साथ ही किसानों को **पीएम-कृषुम योजना** के तहत सौर पैनल स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है, जहाँ किसान अधिषिष बजिली का उपयोग कर सकते हैं और इसे ग्रडि को बेंच भी सकते हैं, जो स्थरिता और समानता को बढ़ावा देगा।
- **उत्सर्जन में कमी:**
  - LED बलब वतलरण योजना (उजाला) पर चर्चा की गई, जो बीते सात वर्षों से चल रही है, जसिने कथति तौर पर 220 बलियिन यूनटि बजिली की बचत की है और प्रतविर्ष 180 बलियिन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोका था।
  - **राषटरीय हाइडरोजन मशिन** का लक्ष्य '**हरति हाइडरोजन**' का दोहन करना है और यह TERA जैसे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों पर नरिभर है कवि मापनीय समाधानों को अपनाए।
- **रामसर स्थल:**
  - **इंटरनेशनल यूनयिन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)** द्वारा भारत के प्रयासों को अंतरराषटरीय मान्यता प्रदान की गई तथा भारत में अब 49 **रामसर स्थल** (आरद्रभूमि) हैं जो 1 मलियिन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्तर में फैली हुई हैं।
    - भारत एक वशिल जैव-वविधिता वाला देश है। वशिव के **2.4% भूमिक्षेत्तर** के साथ भारत में वशिव की लगभग **8% प्रजातियाँ** पाई जाती हैं।
- **भूमिक्षरण:**
  - भूमिक्षरण को रोककर उसकी पुनः बहाली वर्ष 2015 से मुख्य फोकस क्षेत्तरों में से एक रहा है और 11.5 मलियिन हेक्टेयर से अधिक को बहाल किया गया है।
  - भारत **बॉन चैलेंज** के तहत **भूमिक्षरण तटस्थता** की राषटरीय प्रतबिद्धता को प्राप्त करने की राह पर है।
  - भारत यूएनएफसीसीसी (**UNFCCC**) के तहत की गई अपनी सभी प्रतबिद्धताओं को पूरा करने में दृढ़ वशिवास रखता है। भारत **नेलासगो में CoP-26** के दौरान भी अपनी महत्त्वाकांक्षाओं में वृद्धि की है।
    - उदाहरण के लिये भारत ने घोषणा की कविह वर्ष **2070 तक कार्बन तटस्थता** के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।
- **समन्वति कार्रवाई:**
  - सस्टेनेबिलिटी हेतु **ग्लोबल कॉमन्स** के लिये समन्वति कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत के प्रयासों ने इस अंतर-नरिभरता को मान्यता दी है।
    - **अंतरराषटरीय सौर गठबंधन** के माध्यम से भारत का उद्देश्य "**वन सन, वन वरलड, वन ग्रडि**" है।
  - वशिव को हर समय हर जगह **वशि्वव्यापी ग्रडि से स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता** सुनिश्चित करने की दशिा में काम करना चाहिये।
  - इसने देशों से **समानता के सिद्धांतों को ध्यान** में रखते हुए वशि्व स्तर पर सहमत नयिमों के आधार पर कार्य करने तथा **वशि्ववति उत्तरदायित्व एवं संबंधति क्षमताओं के साथ** राषटरीय परस्थितियों के आधार पर जलवायु परविरतन पर कार्य करने का भी आग्रह किया है।
    - जब तक कवि वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचति हसिसे के तहत सभी देशों द्वारा इक्वटी को लागू नहीं किया जाता है तब तक **परसि समझौते** के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता।
- **आपदाग्रस्त द्वीपों के लिये बुनयिादी ढाँचा:**
  - **आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर गठबंधन (C.D.R.I.)** का उद्देश्य लगातार प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्तरों में मज़बूत बुनयिादी ढाँचे का नरिमाण करना है।
  - CoP-26 की तर्ज पर भारत ने "इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेज़िलिएंट आइलैंड स्टेट्स" नामक एक पहल भी शुरू की।
    - द्वीप आधारति राज्य सबसे कमज़ोर हैं और इसलिये उन्हें तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता है।
- **लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनशिपिटिवि) लॉन्च:**
  - LIFE हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिये जीवन-शैली के विकल्प तैयार करने के संबंध में है। LIFE दुनिया भर में समान वचिारधारा वाले लोगों का एक गठबंधन होगा जो स्थायी जीवन-शैली को बढ़ावा देगा।
  - उन्हें 3पी (प्रो प्लैनेट पीपल) कहा जाएगा। यह वैश्विक आंदोलन 'लाइफ' के करयान्वन हेतु एक गठबंधन है।

## सतत् वकिस और जलवायु परविरतन:

- **सतत् वकिस:**
  - सतत् वकिस वह वकिस है जो भवषिय की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता कयि बना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करता है।
  - सतत् वकिस की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परभिषा बरुंटेल्ड आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट '**ऑवर कॉमन फ्यूचर**' (1987) में दी गई थी।
    - सतत् वकिस लक्ष्य (एसडीजी) एक वैश्विक प्रयास है जिसका एक प्रमुख उद्देश्य है - सभी के लिये बेहतर भवषिय प्राप्त करना।
- **जलवायु परविरतन:**
  - यह औसत मौसम पैटर्न में एक दीर्घकालिक परविरतन है जो पृथ्वी के स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु को परभिषति करने के लिये इस्तेमाल किया गया है।
  - जलवायु डेटा रिकॉर्ड जलवायु परविरतन के प्रमुख संकेतकों का प्रमाण प्रदान करते हैं, जैसे कवि वैश्विक भूमि और समुद्र के तापमान में वृद्धि, बढ़ता समुद्र का स्तर, पृथ्वी के ध्रुवों व परवतीय हमिनदों में बरफ का नुकसान, चरम मौसमी आवृत्तति तथा गंभीर परविरतन जैसे-तूफान, हीटवेब्स, वनाग्नाति, सूखा, बाढ़ एवं वर्षा, वनस्पति आवरण परविरतन।

स्रोत: द हट्टि

## डार्कथॉन-2022

### प्रलिमिंस के लिये:

डार्कनेट, डार्कथॉन |

### मेन्स के लिये:

डार्कनेट और इससे संबंधित चर्चाएँ |

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau- NCB) ने साइबर वशिषज्जों के लिये डार्क वेब में गुमनाम बाजारों की पहचान को उजागर करने के लिये प्रभावी समाधान खोजने हेतु एक 'डार्कथॉन' लॉन्च किया है।

- भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के मामले में नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत NCB ने हाल के दिनों में महत्त्वपूर्ण मामलों में सफलता प्राप्त की है।

## प्रमुख बटु

### डार्कथॉन-2022:

- डार्कथॉन-2022 में प्रतभागियों को 'डार्कवेब क्रॉलिंग' के आधार पर सक्रिय नशीली दवा तस्करों तथा उनसे संबंधित नए बाजारों की पहचान करने एवं इनएक्टिवि लोगों को रहिा करने तथा डिजिटल फुटप्रिंटिंग पर दवाओं की बिक्री करने वाले डार्कनेट बाजारों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करने के लिये एक "समाधान" प्रदान करना होगा।
- महामारी के प्रकोप के बाद भारत में पारसल या कूरियर के माध्यम से नशीली दवाओं की बरामदगी में लगभग 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उनमें से एक बड़ी संख्या डार्कनेट बाजारों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी हुई है।

## डार्कनेट और चर्चाएँ:

- परचिय: इंटरनेट में तीन लेयर होती हैं:**
  - पहली लेयर सार्वजनिक होती है, जिसमें ऐसी साइट्स शामिल हैं जिनका प्रायः उपयोग किया जाता है जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, अमेज़न और लकिडइन। यह लेयर पूरे इंटरनेट का केवल 4% भाग है।
  - दूसरी लेयर, डीप वेब एक ऐसा नेटवर्क है, जहाँ डेटा को अप्राप्य डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है (अर्थात् इन तक गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से नहीं पहुँचा जा सकता)। इसका उपयोग लोगों के एक वशिषिट समूह तक पहुँच स्थापित करने के लिये किया जाता है।
    - यह डेटा आमतौर पर संवेदनशील और नजिी होता है (सरकारी नजिी डेटा, बैंक डेटा, क्लाउड डेटा इत्यादी), इसलिये इसे पहुँच से बाहर रखा जाता है।
  - इंटरनेट की तीसरी लेयर 'डार्कनेट' होती है जिसे 'डीप वेब' के एक भाग के रूप में भी जाना जाता है। यह इंटरनेट पर नरिमति एक नेटवर्क है जो प्रायः एन्क्रिप्टेड होता है।
    - यह मूल रूप से इंटरनेट की एक ऐसी परत है जिसे केवल TOR (द ओनयिन राउटर), या 'I2P' (इनवज़िबिल इंटरनेट प्रोजेक्ट) जैसे वशिष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ही चलाया जा सकता है।
    - डार्क वेब पर मौजूद कुछ भी सामान्य इंटरनेट खोज में शामिल नहीं होता है, जिससे काफी अधिक एनॉनमिटी की स्थिति बनी रहती है।
- डार्कनेट से संबंधित चर्चाएँ:**
  - फरवरी 2016 में 'क्रिप्टोपॉलिटिक एंड द डार्कनेट' नामक एक अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने TOR नेटवर्क पर मौजूद कंटेंट का वशिषण किया।
    - 2,723 वेबसाइट्स को उनके कंटेंट के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जिसमें से 1,547 यानी 57% वेबसाइट्स पर ड्रग्स (423 साइट्स), अश्लील साहित्य (122) और हैकगि (96) से लेकर अन्य अवैध सामग्री मौजूद थी।
  - नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग साइट्स के लॉग-इन वविरण को डार्क वेब मार्केटप्लेस पर सस्ते दरों पर बेचे जाने की भी रिपोर्ट है।
  - नेटवर्क का उपयोग कई कार्यकर्त्ताओं द्वारा वशिष रूप से दमनकारी शासन के तहत रहने वाले लोगों द्वारा बना किसी सरकारी सेंसरशिप के संवाद करने हेतु किया जाता है।
  - टीओआर (TOR) नेटवर्क का उपयोग कार्यकर्त्ताओं द्वारा [अरब सप्रगि](#) के दौरान किया गया था।
- डार्कनेट और भारत:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर अपराध से संबंधित है तथा यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत

आता है। साइबर अपराध से नपिटने के लिये कानून में केवल छह धाराएँ हैं।

- बदलते समय के साथ भारत को साइबर अपराध से नपिटने के लिये एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता की आवश्यकता है जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत होगी तथा जो पुलिसिगि के मुद्दों से संबंधित है।
- साथ ही साइबर प्रवृत्तियों में बदलाव हेतु प्रशिक्षित पुलिसि की आवश्यकता है जो केवल साइबर अपराध के लिये समर्पित हो अर्थात् अन्य पुलिसि इकाइयों में स्थानांतरित न हो।

**स्रोत: इकाँनमकि टाइम्स**

---

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/17-02-2022/print>

